



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पोत परिवहन मंत्रालय / MINISTRY OF SHIPPING

नौवहन महानिदेशालय, मुंबई
DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING, MUMBAI

फ.संख्या:- इंजी/ओपीपी-38(02)19

दिनांक:- 16.10.2019

नौमनि आदेश संख्या-05/2019

एकल प्रयोग प्लास्टिकों के प्रयोग पर प्रतिशोध

प्रस्तावना :

जबकि, यथासंशोधित वाणिज्य पोतपरिवहन अधिनियम 1958 का उद्देश्य नौवहन का निरंतर विकास और यह सुनिश्चित करना है कि राष्ट्रीय हितों के अनुरूप सर्वश्रेष्ठ तरीके से भारतीय समुद्री वाणिज्य निरापद तथा प्रभावकारी तरीके से कार्य करें;

2. जबकि नौवहन महानिदेशालय [नौमनि], पोतपरिवहन मंत्रालय, भारत सरकार को यथासंशोधित वाणिज्य पोतपरिवहन अधिनियम 1958 को लागू करने के लिए देश के समुद्रीय प्रशासक के रूप में, भारत में वाणिज्य पोतपरिवहन के सुविधा प्रदाता तथा विन्यामक के रूप में पदनामित किया है।

3. जबकि, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) अग्रणी वैश्विक पर्यावरणी प्राधिकरण है जो वैश्विक रूप से पर्यावरणीय मुद्दे तय करता है, इसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत सतत विकास के पर्यावरणीय आयम के कार्यन्वयन का समर्थन करता है, और वैश्विक पर्यावरण हेतु प्राधिकार पूर्वक इसके समर्थन का कार्य करता है;

4. जबकि, भारत वर्षों से समुद्री प्रदूषण की रोकथाम सहित यूएनईपी के कार्य में सक्रिय सहयोग देता रहा है;

5. जबकि, 'एकल-प्रयोग प्लास्टिक निरंतरता हेतु रूपरेखा' शीर्षक वाली यूएनईपी रिपोर्ट 2018 के अनुसार एकल-प्रयोग प्लास्टिक को निपटान योग्य प्लास्टिक के रूप में भी जाना जाता है, जैसे प्लास्टिक के थैले, स्टॉ, कॉफी स्टिरर्स, सोडा और पानी की बॉतले तथा भोजन समावेशन सामग्री जिनका प्रयोग मात्र एक बार करने के बाद फेंक दिया जाता है या फिर रिसैकिल किया जाता है;

बीटा बिल्डिंग, 9वीं मंजिल, आई थिंक टेक्नो कैम्पस, कांजूर गाँव रोड, कांजूरमार्ग (पूर्व) मुंबई-400042

9th Floor, BETA Building, I-Think Techno Campus, Kanjur Village Road, Kanjurmarg (E), Mumbai-400042

फ़ोन/Tel No.: +91-22-2575 2040/1/2/3 फ़ैक्स/Fax.: +91-22-2575 2029/35 ई-मेल/Email: dgship-dgs@nic.in वेबसाइट/Website: www.dgshipping.gov.in

6. जबकि, पूर्वोक्त रिपोर्ट में इस बात पर बल देकर कहा गया कि हर जगह पाया जाने वाला प्लास्टिक आज सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन गया है जिससे समुद्री जगत में बाधा पहुँचती है। इसके फलस्वरूप कुछ एक समुद्री क्षेत्र प्लास्टिक का दलदल बन गए हैं।

7. अंतर्राष्ट्रीय सफाई रिपोर्ट 2017 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय तटवर्ती सफाई के दौरान जो सबसे आम बातें पता चली हैं, इसका परिमाणात्मक रूप, सिगरेट के टुकड़े, प्लास्टिक की पेय सामग्री वाली बोतलें, प्लास्टिक की बोतलों के ढक्कन, भोजन के रेपर, प्लास्टिक के पर्चून वाले थैले, प्लास्टिक के ढक्कन, स्ट्रॉ और स्टिरर्स, पेय सामग्री के कॉच की बोतलें, अन्य तरह के प्लास्टिक बैग तथा फोम के टेकअवे के डिब्बे, एकल प्रयोग वाले प्लास्टिक, सबसे पहले सूची में आने वाली मदों में इन सबका स्थान सबसे ऊपर रहा है।

8. जबकि, 2018 की युएनईपी रिपोर्ट 'एकल प्रयोग प्लास्टिक निरंतरता हेतु एक रुपरेखा' के अनुसार प्लास्टिक प्रदूषण आज हमारे बीच की एक बड़ी चुनौती है एकल प्रयोग वाले फेंक दिये जाने वाले प्लास्टिक की सबसे बड़ी मात्रा इसमें शामिल होती है, लाखों प्लास्टिक के बैग पर्यावरण में मिलकर मिट्टी, जलाशय, नदियों तथा समुद्रों को प्रदूषित करते हैं

9. जबकि, अंतरराष्ट्रीय समुद्रीय संगठन के अनुसार, समुद्री कूड़े की वजह से हमारे महासागरों में बड़ी समस्या आती है। कुछ बैजानिकों ने चेतावनी दी है कि 2050 तक महासागरों में प्लास्टिक का परिणामण मछलियों से अधिक हो जाएगा

10. जबकि, समुद्र में प्लास्टिक फेके जाने संबंधी प्रतिबंध की बात समुद्री विन्यामक ढाँचे में कोई सर्वथा नई नहीं है।

11. जबकि, अनुभवी लोगों से पता चला है कि समुद्रकर्मियों द्वारा पोत पर जानबूझकर कूड़ा (प्लास्टिक की बातलें, थैले आदि) जमा किया जाता है और उचित शिक्षा तथा प्रबंधन के अभाव से समुद्रकर्मों अपरिहार्य रूप से एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पादों का प्रयोग करते हैं, गैर जिम्मेदार तरीके से फेंक देते हैं।

12 जबकि, इस तरह की आदतों से बचने के लिए आईएमओ ने एक सकल्प दिनांक 07 जुलाई 2017 को एमईपीसी 295 (71)/2017 मारपोल अनुलग्नक V के कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शी सिधांत सकल्प अंगीकृत किया है।

13. जबकि, 15 अगस्त 2019 को स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने आम जनता और सरकारी अभिकरणों से अनुरोध किया और एकल प्रयोग वाले प्लास्टिक से भारत को मुक्त करने की दिशा में पहला बड़ा कदम उठाया।

14. जबकि, आम जनता और सरकारी अभिकरणों के नाम माननीय प्रधानमंत्री के इस आवहन के क्रम में नौवहन महानिदेशक ने यह निर्णय लिया है कि भारतीय समुद्रों में पोतों के रहते समय भारतीय तथा विदेशी पोतों पर एकल प्रयोग वाले प्लास्टिक के प्रयोग पर प्रतिशेध लगाए जाने वाले मुद्दे की जांच की जाए।

15. जबकि, नौवहन महानिदेशक भारत सरकार की अध्यक्षता में 19 अगस्त 2019 को निदेशालय में हितधारियों की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में इन्डियन नैशनल शिप ऑनर्स एसोसिएशन, इन्डियन कोस्टल शिपिंग एसोसिएशन और मान्यप्राप्त संगठनों ने भाग लिया।

16. जबकि, उक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 20 अक्टूबर 2019 से भारतीय नौजगत द्वारा हर संभव प्रयास किया जाएगा कि एकल प्रयोग वाले प्लास्टिक से भारत और भारतीय समुद्रों को मुक्ति प्रदान करने के लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाया जाए।

17. अब इसलिए, व्यापक जनहित में भारतीय समुद्रों में रहते समय भारतीय और विदेशी पोतों पर एकल प्रयोग वाले प्लास्टिक के प्रयोग संबंधी पाबंदी लगाई गई है जिसकी शर्तें और निबंधन अग्रांकित परिच्छेदों में दिए गए हैं।

18. यह प्रतिबंध किस पर लागू होगा

18.1 जिन पोतों को वाणिज्य पोतपरिवहन अधिनियम 1958 के अंतर्गत भारतीय पोत समझा जाता है।

18.2 भारत के किसी पतन या स्थान पर कोई विदेशी पोत।

19. निषेध:

19.1 01.01.2020 से प्रतिशोधित मर्दे निषिद्ध वस्तु:

01.01.2020 से जो पोत भारत के किसी पतन या किसी स्थान पर होंगे, उन भारतीय और विदेशी पोतों पर निम्नोक्त एकल प्रयोग वाले प्लास्टिक का प्रतिशेध है;

19.1.1 थैले, ट्रे, डिब्बे, भोजन समावेशन फिल्म;

19.1.2 दूध की बोतलें, फ्रीजर बैग, शैम्पू की बोतलें, आइसक्रीम के डिब्बे;

- 19.1.3 पानी तथा अन्य पेय की बोतलें, सफाई तरल पदार्थ कंटेनर, बिस्किट ट्रे;
19.1.4 गर्म पेय के कप, इन्सुलेटेड फुड पैकेजिंग, कांच आदि के सामान की सरंक्षी समावेशन सामग्री;
19.1.5 माइक्रोवेव की प्लेटें, आइसक्रीम टब, आलू चिप बैग, बोतल के ढक्कन;

19.2 तत्काल प्रभाव से प्रतिशोधित मद:

- 19.2.1 कटलेरी, प्लेटें और कप;
19.2.2 पानी तथा अन्य पेयों की 10 लीटर तक की बोतलें;
19.2.3 कूड़ा तथा खरीददारी के बैग
19.2.4 10 लीटर से कम की मात्रा वाले क्लीनिंग फ्लूयिड के डिस्पेन्सिंग कंटेनर

20. प्रवर्तन:

20.1 सभी मान्यता प्राप्त संगठनों को एतद्वारा निवेश दिया जाता है कि वे भारतीय पोतों के सर्वेक्षणों, निरीक्षण और लेखा परीक्षा के दौरान अग्रंकित को सुनिश्चित करें।

20.1.1 एकल प्रयोग वाले प्लास्टिक किसी भी भारतीय पोत पर न तो पाए जाएं ना प्रयोग में लाए जाएं, ना ही भंडारित किए जाएं। पोतों की सर्वेक्षण स्थिति में इसी आशय का एक ज्ञापन लगाया जाए।

20.2 भारतीय पोतों का ध्वज पोत निरीक्षण/लेखा परीक्षा/सर्वेक्षण करते समय प्रशासन सर्वेक्षक इस बात का सत्यापन करे कि भारतीय पोतों पर ना तो एकल प्रयोग वाले प्लास्टिक प्रयोग में लाए जाते हैं और न ही उपलब्ध हैं। अनुपालन न करने की दशा में सहिता 99103 (अन्य मारपोल प्रचालनात्मक) के अंतर्गत प्रस्थान करने से पहले ठीक किए जाने के लिए कमी को सामने लाया जाए। अगले निरीक्षण के दौरान यदि यही कमी फिर सामने आती है तो आईएसएम सहिता के अंतर्गत रोके जाने के लिए इसे एक स्पष्ट आधार माना जाए।

20.3 विदेशी ध्वज जलयानों पतनराष्ट्र निरीक्षण करते समय प्रशासन सर्वेक्षक यह सुनिश्चित करें कि भारतीय पतनों में रहने के दौरान तथा भारत के समुद्री मार्ग से आते जाते समय इनमें न तो एकल प्रयोग वाले प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है न ही इन्हें ताला बंद करके भंडार में रखा गया है। भारतीय पतन में आने के इच्छुक भारतीय पोत (यूएनसीएलओएस के अनुच्छेद 11 में बताए गए) से यह अपेक्षा है कि वह पोत पर एकल प्रयोग वाली प्लास्टिक मदों की जानकारी दिए जाने संबंधी प्रविष्टि करें तथा भारतीय समुद्र में घुसने से पहले इन्हें रखे जाने का समय,

अक्षांश, देशांतर बताएं जहां कि इसे रखा गया है। इसके अलावा किसी भारतीय पतन की पतन ग्राही सेवा में एकल प्रयोग के प्लास्टिक वाली किसी मद को न डाला जाए; इसका सत्यापन पतनराष्ट्र निरीक्षणों के समय किया जाए। विदेशी पतनों को रोका न जाए। यदि ऐसा किया जाना आवश्यक हो तो समस्त उन कमियों को आईओसीआईएस की वेबसाइट पर अपलोड किया जाने के बाद प्रस्थान करने से पहले ठीक किए जाने के लिए मुद्रित पतन राष्ट्र नियंत्रण प्रपत्र बी में, कमियों को हाथ से लिख कर जारी किया जाए, तथापि किसी ऐसी कमी को आईओसीआईएस पर अपलोड न किया जाए।

21. पूर्वोक्त उपाय निरापद, सुरक्षित, पर्यापरणीय रूप से सुद्रढ, निरंतर चलते रहने योग्य नौवहन तथा जनहित में किए गए हैं।

22. यह आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया जाता है।



(अमिताभ कुमार)

नौवहन महानिदेशक

एवं अपर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. सभी हितधारकों को डीजीएस वेबसाइट के माध्यम से
2. सभी समुद्री वाणिज्य विभाग
3. सभी मान्यताप्राप्त संगठनों
4. इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन
5. इंडियन नैशनल शिप-ओनर्स एसोसिएशन [INSA], मुंबई
6. ICC शिपिंग एसोसिएशन [ICCSA], मुंबई

सूचनार्थ प्रतिलिपि:

सचिव, भारत सरकार, पोतपरिवहन मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110 001
(ध्यानार्थ: श्री सतिंदर पाल सिंह, संयुक्त सचिव)